बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 143 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 20 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, एलपीजी की किल्लत से रोजेदारों की भी बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर जमीनी हकीकत और आधिकारिक दावों के बीच एक भारी अंतर देखने को मिल रहा है. दिल्ली के गांधी नगर स्थित इंडेन गैस सर्विस पर सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं. एक तरफ गैस एजेंसी किसी भी तरह की शॉर्टेज (कमी) से साफ इनकार कर रही है, वहीं आम जनता घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर है. एजेंसी की काउंटर अटेंडेंट योति ने गैस की किल्लत से इनकार करते हुए बताया, हमारे पास सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है.

ईडी की अर्जी पर केजरीवाल-सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली मोहलत, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (19 मार्च) को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को ईडी की उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया, जिसमें आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में सभी को बरी करते समय विशेष न्यायालय द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सभी आरोपियों को उनके वकीलों के अनुरोध पर समय दिया। ईडी की ओर से सहायक सरकारी वकील एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन उपस्थित हुए। शुरुआत में अभियुक्तों के वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हुसैन ने कहा कि उनके जवाब मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी अभियुक्तों को याचिका की प्रति विधिवत रूप से दी जा चुकी है। राजू ने कहा कि अभियुक्त केवल कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं और यदि एजेंसी के पक्ष में कोई आदेश पारित होता है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। न्यायाधीश ने प्रतिवादियों के वकील से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ अभियोजन पक्ष कह रहा है कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है।

मैंने उन्हें (पिछली तारीख को) बताया था कि मैं भी ऐसी टिप्पणियां करता हूं। मेरा मानना ??था कि मुझे यह तय करना होगा कि न्यायाधीश ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है या नहीं। आप (आरोपी) ने कहा था कि आप जवाब दाखिल करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि आपको 600 पन्ने पढ़ने हैं। आपको एक और हफ्ता चाहिए, तो ले लीजिए। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में जब मामले पर सुनवाई हुई तो अदालत ने केजरीवाल और अन्य को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने कहा कि चूंकि मैंने आदेश पारित कर दिया है, अगर वे कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इसे 2 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया जाए। हम सुनवाई करेंगे और फिर अंतिम आदेश पारित करेंगे। वे (ईडी) शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि आप (प्रतिवादी) उस तारीख को शुरू भी न करें। केवल 2 तारीख को जवाब मांगा गया है। उस दिन कुछ नहीं होगा। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है। ईडी ने कहा है कि वह सीबीआई की कार्यवाही में किसी भी रूप में पक्षकार नहीं थी और प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज किए जाने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति प्राकृतिक न्याय और न्यायिक मर्यादा के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। याचिका में कहा गया ह, ÷यदि इस तरह की व्यापक, अनियंत्रित और निराधार टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, जो प्रवर्तन निदेशालय की पीठ पीछे केवल अनुमानों के आधार पर की गई हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई सामग्री या साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है, क्योंकि इन टिप्पणियों को करते समय न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों से संबंधित नहीं था, तो आम जनता के साथ-साथ याचिकाकर्ता को भी गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

दिल्ली विधानसभा के ई-विधान पोर्टल में जोड़ा गया विधान साथी टैब, विधायकों को तुरंत मिलेगी जानकारी

नई दिल्ली।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार के सत्र में हमने विधायकों के लिए ई-विधान पोर्टल में एक नया टैब जोड़ा है। यह नया टैब विधान साथी के नाम से होगा। इसमें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके विधायक सदन की कार्रवाई से संबंधित जानकारी, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, विधानसभा में हुई चर्चा से संबंधित सभी सामग्री हासिल कर सकेंगे। बहुत ही आसान तरीके से विधायक अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें विधान

साथी की सुविधा विधायकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस बार के विधानसभा सत्र में यह नई सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा प्रयास दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह पेपर लेस रखने पर है। हमने पिछले सत्र में किसी भी विधायक को कोई भी जानकारी हार्ड कापी या पेपर के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई। सारी जानकारी उन्हें आनलाइन ही उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि ई विधान पोर्टल पर पहले से ही अधिकतर जानकारी अपलोड होती रही है। इस बार से विधान साथी के रूप में एक यह नई सुविधा विधायकों के लिए आसान विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी। संक्षिप्त बजट सत्र बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तीन दिन के लिए सत्र बुलाया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बता दें कि तीन दिवसीय विधानसभा के बजट सत्र में 24 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तक सरकार हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए प्रतिनिधियों, डॉक्टर और महिला संगठनों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से बजट को लेकर सुझाव ले चुकी है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा एक लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, लेकिन सरकार एक साल पूरा से पहले जनवरी माह तक बजट का मात्र 42 प्रतिशत पैसा ही विकास योजनाओं में खर्च कर पाई थी। अब देखना होगा कि सरकार इस बार बजट का क्या साइज रखती है और पिछले बचे हुए पैसे का इस्तेमाल कब तक हो पता है।

कंगना रनौत का हाल स्मृति ईरानी जैसा होगा, राहुल गांधी को टपोरी बताने पर बोलीं अलका लांबा

नई दिल्ली। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टपोरी कह दिया. उनके इस बयान की आलोचना हो रही है. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि कंगना रनौत स्मृति ईरानी की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी भी बहुत घमंड में थीं लेकिन सास भी कभी बहू की तरह गायब हो गईं. उनका आज पता नहीं है. कंगना रनौत का भी हाल वही होगा जो स्मृति ईरानी का हुआ. जैसे स्मृति ईरानी राजनीति से गायब हो गईं और उसी तरह कंगना रनौत का भी पता नहीं लगेगा. अलका लांबा ने कहा, ÷राजनीति में शब्दों की नीचता तक वो जा रही हैं. उन्हीं के हिमाचल में उन्हीं के एक विधायक पर नाबालिग बच्चे के बलात्कार में एफआईआर हुई, चार्जशीट हो गया और कोर्ट में पेश होना है. ये बीजेपी का विधायक है. उन्हें कहिए कि उस पर बोलेंगी क्या? आप कुलदीप सिंह सेंगर पर बोलीं? बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, आप बोलीं? पैरोल पर इतने बलात्कारी बाहर आ रहे हैं, आप बोलीं? आप बिल्कुल नहीं बोलेंगीं क्योंकि आप उनके साथ खड़ी हैं कांग्रेस की नेता ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाएं उनसे कितने अपनेपन से मिल रही थीं. महिलाएं भावुक हो रही थीं, गले मिल रही थीं. किसी को असहज महसूस नहीं हुआ. सिर्फ आप ही को क्यों महसूस होता है? सचाई ये है कि एक समय पर आपको नशे की बुरी लत थी. आप नशे में रहीं और उस नशे का असर सालों बाद भी लग रहा है कि जा नहीं रहा है. उस नशे का जो असर है, आज भी आप पर दिखता है कि आप मुद्दों पर नहीं बोलतीं. मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता होती है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति आयोग का तुरंत गठन करें और उसका अध्यक्ष अपनी सांसद कंगना रनौत को बना दें.

मनीष तिवारी का मोदी सरकार को समर्थन, पश्चिम एशिया संघर्ष पर बोले- यह हमारा युद्ध नहीं

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गुरुवार को पश्चिम एशिया संघर्ष पर केंद्र सरकार के संतुलित रुख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में सीमित भूमिका निभाई है और उसे रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए। ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संकट की व्यापकता और जटिलता को देखते हुए नई दिल्ली का सतर्क कूटनीतिक दृष्टिकोण उचित है। तिवारी ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र एक ही युद्ध नहीं बल्कि कई परस्पर विरोधी संघर्षों का गवाह है। उन्होंने कहा कि इज़राइल और ईरान के बीच जो कुछ हो रहा है और अमेरिका का किसी एक पक्ष का साथ देना, केवल मध्य पूर्व की स्थिति का मामला नहीं है... यह हमारा युद्ध नहीं है। हम हमेशा से ही वृहत्तर मध्य पूर्व में हाशिए पर रहे हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत को उन भू-राजनीतिक लड़ाइयों में उलझने से बचना चाहिए जिनका उससे सीधा संबंध नहीं है। संयमित रहने के महत्व पर जोर देते हुए तिवारी ने कहा कि भारत सतर्क रहकर सही कदम उठा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम सतर्क हैं, तो शायद हम सही ही कर रहे हैं, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता का यही अर्थ है - अपने हितों की रक्षा करने और सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता। संकट की शुरुआत से ही भारत ने पूरे क्षेत्र में अपने हितों को संतुलित करते हुए लगातार संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। हालांकि नई दिल्ली ने खाड़ी में ईरानी हमलों की निंदा की, लेकिन उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस के प्रवाह को सुरक्षित करने के लिए तेहरान के साथ संपर्क भी बढ़ाया - यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो वैश्विक ऊर्जा शिपमेंट के लगभग पांचवें हिस्से को संभालता है। संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के अंदर समन्वित हमले किए, जिसमें कई स्थानों पर लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में वाशिंगटन और यरुशलम से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई। इस बीच, भारत खाड़ी क्षेत्र में हो रही अस्थिरता पर कड़ी नज़र रख रहा है, क्योंकि यह अस्थिरता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने और काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है।

गंभीर ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, एआई-डीपफेक के गलत इस्तेमाल पर रोक की लगाई गुहार

नई दिल्ली ।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। इस केस में उन्होंने डिजिटल नकल, एआई से बनाए गए डीपफेक और बिना अनुमति उनके नाम, चेहरे और आवाज के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बने कई फर्जी अकाउंट

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने गंभीर की लीगल टीम के हवाले से बताया कि, 2025 के अंत से इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से नकली कंटेंट तेजी से बढ़ा है। एआई, फेस-स्वैपिंग और वॉइस-क्लोनिंग तकनीक की मदद से ऐसे वीडियो बनाए गए, जिनमें उन्हें ऐसे बयान देते हुए दिखाया गया जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं। इनमें एक फर्जी इस्तीफे का वीडियो भी शामिल था, जिसे लाखों बार देखा गया। मामले में 16 पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे एमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा टेक कंपनियां जैसे मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल और यूट्यूब का नाम भी इस केस में है। आईटी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि कोर्ट के आदेशों को लागू कराया जा सके।

2.5 करोड़ का हर्जाना मांगा

यह मुकदमा कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 और कॉमर्शियल एक्ट 2015 के तहत दायर किया गया है। इसमें पहले दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जैसे अमिताभ बच्चन बनाम रजत नेगी, अनिल कपूर बनाम सिम्पली लाइफ इंडिया और सुनील गावस्कर बनाम क्रिकेट तक, जिनमें पर्सनैलिटी राइट्स को कानूनी सुरक्षा दी गई है। गंभीर ने कोर्ट से 2.5 करोड़ रुपये का हर्जाना, सभी आपत्तिजनक अकाउंट्स को हटाने, भविष्य में ऐसे इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाने और मौजूदा कंटेंट को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस मामले में जल्द सुनवाई की अपील भी की है। इस पर गंभीर ने कहा कि उनकी पहचान और छवि का गलत इस्तेमाल कर फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है और इससे कमाई की जा रही है। उन्होंने इसे सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि कानून और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया, जो एआई के दौर में हर सार्वजनिक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है।

भविष्य के युद्धों में ड्रोन अहम, भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा- राजनाथ सिंह

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (जीआईएससी) के 14वें संस्करण की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज 100 से अधिक चुनौतियों के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (डीआईएससी) का 14वां संस्करण भी शुरू किया गया है। डीआईएससी की अब तक की सफलता को देखते हुए, हमारे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पहली बार 100 से अधिक चुनौतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। मैं डीआईएससी के नए संस्करण के लिए सभी नवप्रवर्तकों को शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को रक्षा निर्माण की सप्लाई चेन से जोड़ना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब छोटे उद्योग बड़े रक्षा कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे, तभी देश में नई खोज और तकनीक की रफ्तार तेज होगी। किसी भी देश के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में बड़े उद्योगों के साथ-साथ स्टार्टअप, स्टार्टअप और इनोवेटर्स की भूमिका बहुत अहम होती है। इसमें सरकार की स्पष्ट नीतियां भी बड़ा योगदान देती हैं। उन्होंने कहा दुनिया के मौजूदा हालातों पर बात करते हुए राजनाथ सिंह ने

रूस-यूक्रेन और ईरान-इस्राइल के बीच चल रहे युद्ध का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया इन संघर्षों को देख रही है। इनसे यह साफ हो गया है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक की भूमिका सबसे यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए भारत को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा, जिसमें हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ अंतिम उत्पाद तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

हमें ड्रोन के हर पुर्जे को भारत में ही बनाना होगा। ड्रोन का ढांचा (मोल्ड), सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि यह काम आसान नहीं है। आज दुनिया के कई देश ड्रोन बनाने के लिए जरूरी पुर्जे चीन से मंगवाते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती के लिए हमें ड्रोन निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने आधुनिक तकनीकों जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि ये तकनीकें पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बदल रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत स्वदेशी ड्रोन निर्माण का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र (ग्लोबल हब) बन जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मिशन में सरकार हर संभव मदद और सहयोग देगी।

अब चुनाव में भ्रष्टाचार हमारी आदत बन चुकी है

''सर, मैं आपको 200 परसेंट बता सकता हूं। चुनाव की घोषणा 14 मार्च से पहले नहीं होगी। और ये भी बता दूं, बाकी राज्यों में चाहे जब हों, असम में चुनाव 14 अप्रैल से पहले हो जाएंगे। आप लिख लीजिए।'' यह बात कोई 2 सप्ताह पहले की है। हम असम में सड़कों की खाक छान रहे थे। मैं सोच रहा था कि पिछली बार की तरह 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा फरवरी के अंत या मार्च के पहले 1-2 दिन में हो जाएगी। जब नहीं हुआ तो असम के एक राजनीतिक कार्यकर्ता को फोन किया। उसने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ''देखिए सर, पी.एम. असम में 13 या 14 तारीख को आने वाले हैं। वह आकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। चुनाव आयोग उनका इंतजार करेगा, उसके बाद आचार संहिता लगाएगा। लेकिन उसके बाद असम में जल्दी से चुनाव करवाए जाएंगे। चूंकि इस बार बिहू के दौरान हर जगह जुबिन गर्ग की फोटो लगेगी, उसके गाने बजेंगे, जो लोगों को याद दिलाएंगे कि सरकार ने जुबिन की मौत की जांच नहीं करवाई। इसलिए भाजपा चाहती है कि 14 अप्रैल को बिहू शुरू होने से पहले-पहले चुनाव पूरे हो जाएं।'' और हुआ भी वही जो उसने कहा था। प्रधानमंत्री मोदी 13 और 14 मार्च को असम आए। दो दिन में उन्होंने असम के विकास के लिए दर्जनों योजनाओं की घोषणा की। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त प्रदान की, चाय बागान के मजदूरों को जमीन का पट्टा बांटा, 3 नई रेलगाड़ियां शुरू कीं, सिल्चर से शिलांग के एक्सप्रेस-वे का भूमि पूजन किया, एक नई जल-विद्युत परियोजना का समर्पण किया। कुल मिलाकर चुनाव की घोषणा से पहले 47,800 करोड़ रुपए बांटे। और हर भाषण में कांग्रेस की पिछली सरकार को कोसा। उसके ठीक अगले दिन, यानी 15 मार्च को, चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी और आचार संहिता लागू हो गई। खबर है कि चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस जुगलबंदी पर किसी को हैरानी नहीं हुई। इतना तो चलता ही है। हमें आदत पड़ चुकी है। हमें आदत इस बात की भी पड़ चुकी है कि चुनाव से ठीक पहले सीधे वोटर के खाते में रिश्वत भेजी जाएगी। इस नई परंपरा का पालन करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के कल्याण की चिंता दर्शाई। राज्य सरकार की अरुणोदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की 40 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस बार महिला कल्याण की विशेष इच्छा के चलते उन सभी महिलाओं के खाते में एकमुश्त 9,000 रुपए डाल दिए गए, 6 महीने का अग्रिम भुगतान और साथ में बिहू का बोनस भी। जाहिर है इस साल का बिहू कुछ विशेष है। साथ ही पिछले महीने बेरोजगार युवाओं को 'जीवन प्रेरणा' देने के लिए एकमुश्त 2,500 रुपए दिए गए। इस प्रेरणा के पीछे क्या प्रेरणा थी, इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। रेवड़ी संस्कृति पर नाक-भौं सिकोड़ने वाले मीडिया ने नहीं, इस प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं। इतना तो चलता ही है। हमें आदत पड़ चुकी है। आजकल हमें इस बात की आदत भी पड़ चुकी है कि चुनाव आएंगे तो झूठ की आंधी लाएंगे, नफरत बरसाएंगे, खून के छींटे आएंगे। इस मामले में इस बार हिमंत बिस्वा सरमा ने योगी आदित्यनाथ को भी मात दे दी। सरमा ने खुल कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान 'मियां' लोगों का वोट कटवाने का आह्वान किया, यह दावा भी किया कि उनकी पार्टी ने 5 लाख मियां के खिलाफ आपत्ति दायर की है। यही नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के बंगला भाषी मुस्लिम नागरिकों का आर्थिक बायकॉट करने की अपील की। कहा कि मियां रिक्शा वाले को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, उन्हें हर तरह से तंग करो। एक टी.वी. चैनल के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि उन्हें पता है कि वह कानूनी तरीके से बंगाली मुसलमान को असम से डिपोर्ट नहीं कर सकते। ''इसलिए मैं प्रैशर बनाता हूं ताकि वे खुद-ब-खुद चले जाएं।'' अगर इतने से भी किसी को समझ ना आया तो असम भाजपा ने एक वीडियो बनाया, जिसमें सरमा के हाथ में पिस्तौल है और निशाना मियां नुमा मुसलमान और उसके साथ बैठे कांग्रेस नेता पर है। कुछ लोगों को अभी इतनी नंगई की आदत नहीं पड़ी थी, इसलिए उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया तो वीडियो को चुपचाप हटा लिया गया। घृणा फैलाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। असम के कुछ बुद्धिजीवियों को अभी आदत नहीं पड़ी थी। नादान थे, इसलिए मुख्यमंत्री के बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। दिन-रात हर छोटे-बड़े मामले में हाथ डालने को तत्पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरंग गुवाहाटी हाईकोर्ट वापस भेज दिया। उन्हें भी आदत पड़ जाएगी। एक आदत अभी हमें नहीं पड़ी है। अमरीका में उसे जेरीमैंडरिंग कहते हैं। यानी चुनाव क्षेत्र की सीमाएं ऐसी बनाई जाएं कि एक पार्टी की विजय पक्की हो जाए। हमने अमरीका से सब कुछ सीख लिया था, लेकिन अभी विकास के इस पायदान तक नहीं पहुंचे थे। असम ने इस बंधन को भी तोड़ दिया। वर्ष 2023 में असम के लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हुआ। आदेश लिखा चुनाव आयोग ने लेकिन उसका भावार्थ समझाया मुख्यमंत्री ने। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि इस परिसीमन के माध्यम से मियां मुसलमान का चुनावी असर कम किया जाएगा। और वही हुआ।

चुनाव आयोग ने अजीबो-गरीब तरह के क्षेत्र बनाए, कोई सांप जैसा तो कोई केंकड़े के आकार का। नतीजा यह हुआ कि पहले असम की 126 सीटों में से 29 पर मुस्लिम बाहुल्य था और इस बार उसके बढ़ने की संभावना थी। लेकिन अंततः ऐसे क्षेत्र घटकर 22 रह गए। अभी बाकी देश को इसका पता नहीं है, आदत नहीं पड़ी है। लेकिन आदत का क्या है, पड़ जाएगी! हिंदी के कालजयी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने 'अंधेरे में' जीने का असर समझाया था-अंधेरे में, सब कुछ जैसे स्वाभाविक लगता है-अन्याय भी, अत्याचार भी, शोषण भी, भ्रष्टाचार भी। अंधेरे में, आदमी धीरे-धीरे सब कुछ सहने का अभ्यास कर लेता है और फिर, उसे लगता है 'कि यही जीवन है।'

प. बंगाल की राजनैतिक लड़ाई

संसद के बजट सत्र के चालू रहते ही चुनाव आयोग ने देश के चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु व प. बंगाल सहित केन्द्र प्रशासित क्षेत्र पुदुचेरी में विधान सभा चुनावों की घोषणा करके इनमें आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया है अतः स्वाभाविक है कि इन चुनावों के लिए होने वाली राजनैतिक लड़ाई की प्रति ध्वनियां हमें संसद से लेकर सड़क तक सुनाई पड़ने लगी हैं। इस सिलसिले में लोकसभा के आठ विपक्षी सांसदों की बहाली को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है जिन्हें बजट सत्र के प्रथम चरण के दौरान सदन में अवांछित आचरण के लिए अध्यक्ष ने पूरे बजट सत्र में संसद की शेष बैठकों में शामिल होने से रोक दिया था। लोकतन्त्र में ऐसी कार्रवाई का समर्थन इसलिए आम तौर पर नहीं किया जाता है क्योंकि एक सांसद अपने क्षेत्र के लाखों लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और भारत का लोकतन्त्र सहभागिता का लोकतन्त्र कहलाता है अतः सदन से सांसदों का निलम्बन आम जनता की सहभागिता को ही नकारने का काम करता है अतः आठ सांसदों की बहाली का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे भारतीय लोकतन्त्र में आम जनता के समुचित प्रतिनिधित्व के रूप में लिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने जिन राज्यों में इनकी विधानसभाओं के कार्यकाल के पांच साल पूरे हो जाने पर समय रहते चुनाव कराने की घोषणा की है वह लोकतन्त्र की सदैव जीवन्तता को शिखर पर रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। जिन चार राज्यों में चुनावों की घोषणा की गई है उनमें सबसे अधिक चर्चा प. बंगाल की इसलिए हो रही है क्योंकि केन्द्र में 2014 में भाजपा की मोदी सरकार गठन होने के बाद 2016 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से इस प्रदेश की राजनीति में आधारभूत परिवर्तन हुआ है। राज्य में भाजपा एक शक्तिशाली राजनैतिक दल के रूप में उभरी है और इसने इससे पूर्व राजनैतिक धुरी रहे वामपंथी दलों को नैपथ्य में धकेल दिया है। हालांकि 2011 के चुनावों में राज्य की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी दलों के लम्बे शासन का खात्मा करके सत्ता की बागडोर संभाल ली थी । इन चुनावों में भाजपा को मात्र चार प्रतिशत मत ही मिले थे मगर 2016 के चुनावों में इनमें कई गुना वृद्धि हुई और वामपंथी दलों की जगह इस पार्टी ने एक विकल्प के रूप में ले ली। पिछले 2021 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस बेशक 294 सदस्यीय विधानसभा में दो तिहाई से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही मगर भाजपा ने उससे लगभग छह प्रतिशत मत कम लेते हुए 77 सीटें जीत लीं।

इससे भाजपा में तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र विकल्प बनने की जिजीविषा जागृत हुई। इसी वजह से हम आज देख रहे हैं कि भाजपा सुश्री ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। मगर यह काम इतना आसान भी नहीं है जितना भाजपा के नेता सोच रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति शुरू से ही लोकोन्मुख रही है और वह सीधे सड़क पर संघर्ष करके जन नेता बनी हैं। पिछले 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी इस राजनैतिक कला का परित्याग नहीं किया है और हर संवेदनशील मौके पर वह आम जनता के बीच ही संघर्ष करती नजर आयी हैं। इसके साथ यह भी हकीकत है कि भाजपा ने इस राज्य में ममता दीदी के ही संगठन से कुछ मजबूत समझे जाने वाले स्तम्भों को अपने संगठन में लेकर सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध अलख जगाने का भगीरथ प्रयास किया है । इनमें 2020 से पहले तक ममता बनर्जी के खास सहयोगी माने जाने वाले नेता सुवेन्दु अधिकारी का नाम सबसे प्रमुख है जो फिलहाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। पिछले 2021 के चुनावों में राज्य की नन्दीग्राम सीट पर ममता दी व अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था जिसमें ममता दी मात्र 1900 से कुछ अधिक वोटों से हार गई थीं। बाद में उन्होंने कोलकोता क्षेत्र में पड़ने वाली भवानीपुरा सीट से उपचुनाव लड़कर 58 हजार मतों से जीत दर्ज की थी। परन्तु राज्य में हुए हाल ही में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इस क्षेत्र के 47 हजार के लगभग मतदाताओं का नाम कट गया है जबकि सुवेन्दु अधिकारी ने नन्दी ग्राम के साथ ही भवानीपुरा से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। परन्तु ममता दीदी ने भी इस बार अधिकारी को नन्दीग्राम में ही घेरने की रणनीति को अंजाम दे दिया है और दो दिन पहले तक उनके परम विश्वास पात्र रहे पवित्र कार को नन्दीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता दीदी ने सुबह पवित्र कार को अपनी पार्टी में शामिल किया और शाम को उन्हें नन्दीग्राम से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे यह अन्दाजा तो लग सकता है कि राज्य की राजनीति में विचारधारा का अब वह महत्व नहीं रह गया है जिसके लिए कभी प. बंगाल जाना जाता था बल्कि अब यह 'जैसे को तैसा' के स्तर पर आ गई है। प. बंगाल में होने वाले चुनावी रण में इस बात की परख पुनः होगी कि राज्य में मतदान पूरे शान्तिपूर्ण माहौल में हो पाता है कि नहीं क्योंकि चुनाव आयोग ने मतदान तारीखों की जानकारी देने के तुरन्त बाद ही समूचे राज्य प्रशासन को बदलते हुए मुख्य सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक व अन्य वरिष्ठतम अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं जिस पर ममता बनर्जी ने सख्त आपत्ति भी दर्ज कराई है । इन परिस्थितियों से भी प. बंगाल के चुनावों का शेष अन्य तीन राज्यों के मुकाबले महत्व बढ़ गया है। लेकिन इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि भवानीपुरा सीट से ममता बनर्जी और सुवेन्दु अधिकारी का मुकाबला किस मोड़ पर आकर ठहरेगा। इस बार भाजपा ने सुवेन्दु अधिकारी को इस सीट से ममता बनर्जी से पहले ही अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया था जबकि ममता दी ने उनका मुकाबला करने की घोषणा बाद में की। पिछले 2021 के चुनावों में ठीक इसका उल्टा हुआ था। अतः हम इसी राज्य में हम सबसे भीषण चुनावी संघर्ष देखेंगे।

सम्पादकीय...

आदत बनता सोशल मीडिया, लगाम आवश्यक

बचपन की मासूमियत निगलती सोशल मीडिया की लत विश्व भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। बच्चों तथा किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रयोग संबंधी पाबंदी लगाने की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती हुई फ्रांस, इंडोनेशिया, स्पेन, नार्वे, ग्रीस जैसे कई देशों तक जा पहुंची है। गत दिनों भारत के आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक भी इस मुद्दे पर आवाज उठाते नजर आए। तेलुगु देशम पार्टी (टेदेपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 13 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की बात कही, जबकि कर्नाटक सरकार की घोषणा अनुसार, निर्धारित आयु सीमा 16 वर्ष होगी। वैश्विक नैटवर्किंग, व्यापक व्यापार तथा विपणन अवसरों, सहज अंतःक्रिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सूचना साझाकरण में बहु-उपयोगी सिद्ध हो रहे सोशल मीडिया का दरअसल, एक स्याह पक्ष भी है, जिसमें गोपनीयता संबंधी चिंताएं, ध्यान भटकना, गलत सूचना और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं। विशेषकर बच्चों तथा किशोरों में सोशल मीडिया के प्रति अनवरत बढ़ता आकर्षण न केवल लत बनकर उनकी सेहत निगल रहा है, अपितु असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में सेंध लगाने का जरिया भी बन रहा है। मनोवैज्ञानिकों एवं बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय में, सोशल मीडिया का अनियंत्रित उपयोग बच्चों के मानसिक तथा भावनात्मक विकास को बहुत प्रभावित कर सकता है। मस्तिष्क विकास के दृष्टिगत किशोरावस्था का प्रारंभिक चरण अत्यधिक संवेदनशील होता है, जोकि सामाजिक दबावों, साथियों के विचारों आदि से काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। वास्तव में, सोशल मीडिया का लगातार उपयोग भावनाएं-आवेग नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों में विशेष परिवर्तन ला सकता है, जिससे सामाजिक संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने से हृदय अधिक भावुक या दुखी हो सकता है। ऑनलाइन धमकाया जाना अथवा साथियों का दबाव (पीयर प्रैशर) किशोरों को तनाव अथवा आत्मघाती विचारों की ओर मोड़ सकता है। आधुनिक बच्चों के व्यवहार में अधीरता, आक्रामकता, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण बहुतायत में देखे जा सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक खेल-कूद से दूरी, परिवर्तित लाइफ स्टाइल एवं बढ़ता स्क्रीन टाइम इसमें प्रमुख कारण हैं। यद्यपि पूर्णतः प्रमाणित नहीं, तथापि कुछ शोधों के तहत, सोशल मीडिया का उपयोग अवसाद तथा चिंता जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी सर्केडियन रिदम को बाधित कर सकती है। देर रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से नींद का पैटर्न गड़बड़ा सकता है। बहुत अधिक समय बिताने से एकाग्रता में कमी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। 2020 में हुए अध्ययन के अनुसार, एक माह के लिए अपना फेसबुक अकाउंट निष्क्रिय करने वाले कुछ लोगों ने अवसाद तथा चिंता में कमी के साथ-साथ खुशी और जीवन संतुष्टि में बढ़ोतरी होने की सूचना दी। सोशल मीडिया का निकृष्टतम पहलू है, साइबर बुलिंग अथवा साइबर धोखाधड़ी, जिसमें यौन शोषण से लेकर वित्तीय ब्लैकमेल के लिए अंतरंग छवियों को वितरित करना आदि शामिल है।

इजराइल-ईरान युद्ध रोकने में क्या होगी भारत की भूमिका

फिरोज बख्त अहमद

मध्य पूर्व एशिया में इस युद्ध को समाप्त करने की पहल के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल व अन्य शांतिप्रिय नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि वे आगे आएं और अमेरिका, इजराइल व ईरान पर दबाव बनाएं और शांति की पहल करें। जहां दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है, वहीं आज तक लोगों की समझ में यह नहीं आया कि आखिर इस युद्ध को ईरान पर क्यों थोपा गया। हाल ही में, जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल भंडारण, अर्थात् खार्ग टापू पर हमला करके उसके हॉर्मुज जलडमरू पर कब्ज़ा करने की बात कही है और सात देशों से अपनी नौसेना भेजने को कहा है, उससे इस ज्वलंत युद्ध के रुकने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं! ईरान पर, खाड़ी के जहाजों पर हमला करने का आरोप लगा है, जिससे हॉर्मुज जल-डमरू-मध्य को प्रभावी रूप से बंद करने की नौबत आ गई है। यह एक अहम रास्ता है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ओमान के दुक्म कमर्शियल बंदरगाह व एमिरात के फुजैराह टर्मिनल सहित प्रमुख तेल व गैस केंद्रों पर हमले हुए हैं। एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) सुविधाएं, तेल व गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था व जीवन-यापन की लागत पर पड़ने वाले असर के बारे में चेतावनियां जारी की गई हैं। पिछले दिनों सैन्य विशेषज्ञों ने कुछ बड़े ही डराने विचार व्यक्त किए, जिनमें ट्रंप और नेतन्याहू की ओर से बात आई कि वे ईरान के ऊपर एटम बम दागने की धमकी दी है। गैस के अभाव में लिए देश और मानवतावादी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जब उसके पास एटम बम नहीं है तो इज़राइल ने ईरान पर हमला क्यों किया और यह युद्ध कब समाप्त होगा।अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू करने के उपरांत 28 फरवरी, 2026 को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के साथ, पूरे मध्य-पूर्व में संघर्ष शुरू हो गया है। ईरान ने इज़राइल व खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले की जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। ये हमले अब दोनों ओर से गैर-सैन्य लक्ष्यों तक फैल गए हैं, जिनमें नागरिक स्थल व ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। अमेरिका-इज़राइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने राजधानी तेहरान व पूरे देश में ईरानी मिसाइल के बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकानों व नेतृत्व को निशाना बनाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई, जो 1989 से देश का नेतृत्व कर रहे थे, हमलों की पहली लहर के दौरान शहीद कर दिए गए। इज़राइली सेना ने बताया कि इस्लामिक आईआरजीसी (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) के दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। खामेनेई की मृत्यु के बाद उनके बेटे, मोजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके बारे में भी अटकलें हैं कि पता नहीं, जीवित हैं या नहीं। 13 मार्च को अमेरिकी रक्षा सचिव, पीट हेगसेथ ने कहा कि नए हमलों में मोजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं, टांगों से मजबूर हो गए व संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया है। उन्होंने इशारा किया कि हाल के हफ्तों में वे सार्वजनिक रूप से देखाई नहीं दिए। तेहरान ने हेगसेथ के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि नए सर्वोच्च नेता के साथ कोई समस्या नहीं है। ऐसा ही उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई के ऊपर जान लेवा हमले के बाद कहा था, मगर वे बाद में मृत घोषित किए गए। अमेरिका-इज़राइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख स्थलों को निशाना बनाना जारी रखा है। यह भी समझ से बाहर है कि जब पिछले वर्ष अमेरिका ने ईरान पर भयंकर हमला कर उसके एटमी कारखानों को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने की बात कही थी और ईरान का मानना था कि वह एटम बम बना ही नहीं रहे तो अब उसपर ताबड़तोड़ हमले क्यों, जिनमें हजारों बेगुनाह ईरानी शहरी मारे गए, जिन में एक प्राइमरी स्कूल की बच्चियां भी हैं ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। हाल के दिनों में इन दोनों ने ईरानी तेल रिफाइनरियों पर हमले तेज़ किए हैं। अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर ध्यान केंद्रित किया, जहां एक बड़ा टर्मिनल है जिसे ईरान की आर्थिक जीवनरेखा माना जाता है। अमेरिका स्थित समूह ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान ने बताया कि ईरान में 3,040 लोग मारे गए हैं, जिनमें 1,122 सैन्यकर्मी व 1,319 नागरिक शामिल हैं, जिनमें 206 बच्चे थे। 599 अन्य मौतें अवर्गीकृत नागरिक व सैन्य थीं। अभी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि 1,300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान ने अमेरिका-इज़राइल पर 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान में आईआरजीसी बेस के पास एक लड़कियों के स्कूल पर हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि लगभग 110 बच्चों सहित 168 लोग मारे गए। अमेरिका ने कहा कि वह इस घटना की जांच कर रहा है, जबकि इज़राइल ने कहा कि उसे उस इलाके में किसी भी सैन्य अभियान की जानकारी नहीं है। विशेषज्ञों के वीडियो विश्लेषण से पता चलता है कि एक अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल स्कूल के पास एक सैन्य अड्डे पर गिरी थी, व बीबीसी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को अब डेमोक्रेट्स की ओर से अमेरिका की संभावित संलिप्तता को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए ईरान में पहुंच सीमित है व देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अपने क्षेत्र के बाहर, 4 मार्च को श्रीलंका के तट के पास हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा, एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया था। इसमें कम से कम 87 लोग मारे गए थे। ईरानी स्कूल के पास मौजूद मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरी। वीडियो एनालिसिस से पता चला कि रात दिन में बदल गई। तेहरान की तेल सुविधाओं पर हवाई हमलों की वजह से काली बारिश हो रही है। ईरान ने इज़राइल के हमलों को बिना किसी उकसावे के, गैर-कानूनी व नाजायज़ बताया है व इसके जवाब में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं। 15 मार्च तक, इज़रायली अधिकारियों ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से मिसाइल हमलों में 12 नागरिक मारे गए हैं। जिन देशों में भी हमले हुए हैं वहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, कतर, बहरीन, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात व कुवैत। 14 मार्च तक, अमेरिकन सेना के 13 जवान मारे जा चुके थे। ईरान पर आरोप है कि उसने अपने हमलों का दायरा दूसरे लक्ष्यों तक बढ़ा दिया है, जिनमें तेल सुविधाएं, जहाज़ व आम नागरिकों से जुड़े स्थान हैं, जैसे दुबई के होटल शामिल हैं। उत्तरी इराक में एक कुर्द मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक मारा गया। इराक में ही पीएमएफ (पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज), जिसे पिछले दशक में 'इस्लामिक स्टेट समूह' से लड़ने के लिए बनाया गया था, बताया कि उसके 27 सदस्य मारे गए हैं। ईरान-इराक में इस्लामिक प्रतिरोध' आईआरआई के बैनर तले काम करने वाले मिलिशिया, आतंकी समूहों का समर्थन करता है, जो पीएमएफ का हिस्सा हैं। अंततः यह कहा जा सकता है, कि यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और इसे तृतीय विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर विश्व को ग्लोबल विलेज व वसुदेव कुटुम्बकम का आह्वान है व दूसरी ओर अमेरिका-इज़राइल, दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों को हड़पना चाहते हैं।

'यह युद्ध का युग नहीं है'

ड्वाइट डी.आइजनहॉवर जो द्वितीय विश्वयुद्ध में यूरोप में सुप्रीम कमांडर थे और बाद में अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति बने ने कहा था, «मैं युद्ध से नफ़रत करता हूं क्योंकि मैंने उसका अनुभव किया है। मैंने उसकी क्रूरता, निरर्थकता और मूर्खता देखी है»। आज जबकि एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यपूर्व में एक और युद्ध शुरू कर दिया है, आइजनहॉवर के इन शब्दों की सार्थकता समझ आती है। ट्रम्प की मूर्खता की बात करने से पहले यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में एक और युद्ध भी चल रहा है। चार साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अनुमान है कि दोनों तरफ़ से मारे गए की संख्या 500000-600000 के क़रीब है। घायल लाखों में है। यूक्रेन छोटा है इसलिए तबाही अधिक हुई है पर रूस का भी भारी नुक़सान हुआ है। क़र्ज़ा बहुत बढ़ गया है और इतने सैनिक हताहत हुए हैं कि भाड़े के सैनिक लेने पड़ रहे हैं। पर युद्ध का कोई अंत नज़र नहीं आता। पुतिन की मूर्खता ने भारी तबाही मचा दी है। हम इस मामले में समझदार रहे हैं। हमारा इतिहास साक्षी है कि हमने दूर-दूर तक अपना प्रभाव फैलाया पर युद्ध के बल पर नहीं। विचारों के बल पर हमने दुनिया को जीता था। ऑपरेशन सिंदूर भी सीमित लक्ष्य के लिए था, हम पाकिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना चाहते थे। यह हमने कर दिया। अगर दूसरे दिन पाकिस्तान जवाब न देता तो युद्ध पहले ही ख़त्म हो जाता। यहां कई लोग, जिन में भाजपा के समर्थक अधिक हैं, ने सरकार की आलोचना की थी कि इतनी जल्दी युद्ध क्यों बंद कर दिया? पर हमारी सरकार ने समझदारी दिखाई। हम जानते हैं कि युद्ध क्रूर, निरर्थक और मूर्ख है इसलिए पाकिस्तान की प्रार्थना को तत्काल स्वीकार कर युद्ध विराम कर लिया। 1971 के युद्ध में हमने ज़रूर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बनवा दिया। पर जब लक्ष्य पूरा हो गया तो इंदिरा गांधी ने शिमला में ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की बात मान ली। उनके 90000 सैनिक वापिस कर दिए और पश्चिम में विजय किया उनका क्षेत्र वापिस कर दिया क्योंकि हम लम्बे युद्ध में फंसना नहीं चाहते थे। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था। मध्य पूर्व में वर्तमान युद्ध के बारे तो पता ही नहीं कि लक्ष्य क्या है? डॉनल्ड ट्रम्प को ख़ुद नहीं पता कि लक्ष्य क्या है इसीलिए बार बार लक्ष्य बदल रहे हैं। हां, एक व्यक्ति ज़रूर है जिन्हें पता है कि लक्ष्य क्या है। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध लम्बा चले। उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए उन्हें युद्ध चाहिए। पहले गाजा को तबाह किया। औचित्य था कि हमास ने 1200 इज़राइली नागरिकों का अपहरण कर मार डाला। हमास एक आतंकी संगठन है पर उस इज़राइल के बारे क्या कहा जाए जिसने बदला लेने के लिए गाजा में 70000 निरपराध लोगों को मार डाला? अस्पताल, स्कूल सब तबाह कर दिए। अभी भी प्यास नहीं बुझी। अब लेबनान को तबाह करने में लगे हैं। कुछ पाठक मुझ से नाराज़ हैं कि मैं मध्य पूर्व में इज़राइल की नीति का विरोध कर रहा हूं। उनका कहना है कि इज़राइल हमारा मित्र देश है। पर जब मित्र उन्मादी हो जाए तो दूरी बनाना ही समझदारी है। नेतन्याहू के उकसावे पर ही ट्रम्प ने मध्य पूर्व में युद्ध शुरू करने की मूर्खता की है। उनका भी पुतिन जैसा अनुमान था कि युद्ध जल्द ख़त्म हो जाएगा।अब वह युद्ध ख़त्म करना चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा। वह 'विक्टरी' बता कर अमेरिका के लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं जहां 60 प्रतिशत लोग इस फ़िज़ूल युद्ध के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए 'विक्टरी' की परिभाषा बदलते जा रहे हैं। नुक़सान को जीत में बदलने पर माथापच्ची हो रही है। न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि कि ट्रम्प फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि युद्ध जारी रखें या जीत का दावा कर पीछे हट जाएं। ट्रम्प को घबराहट है कि संसद के मध्यावधि चुनावों में उनकी पार्टी की हार हो सकती है। युद्ध को लेकर ट्रम्प की बौखलाहट इतनी है कि उनका कहना है कि अमेरिका का मीडिया और बड़े समाचार पत्र चाहते हैं कि अमेरिका युद्ध हार जाए! इस बौखलाहट का बड़ा कारण है कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए वह युद्ध की दलदल में कूद पड़े। जब युद्ध शुरू किया गया तो उन्होंने सोचा था कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा और ईरान की राजनीतिक और सैनिक लीडरशिप बदल जाएगी। पर खामेनेई और बड़े कमांडरों की हत्या के बावजूद ईरान नहीं झुका। उल्टा उसके हमलों की तीव्रता बढ़ गई है। सभी खाड़ी के देश उसके हमले झेल रहे हैं और हॉर्मुज का जलमार्ग उसके नियंत्रण में है। वहाँ से वही जहाज़ निकल रहें हैं जिन्हें ईरान निकलने की इजाज़त दे रहा है। ट्रम्प का तब तक 'विक्टरी' का दावा खोखला रहेगा जब तक हॉर्मुज नहीं खुलता।ट्रम्प अब साथी देशों से गुहार कर रहे हैं कि वह इस जलमार्ग को खुला रखने के लिए अपने युद्धपोत भेजें। अर्थात वह युद्ध को आउटसोर्स करना चाहते हैं पर कोई भी देश तैयार नहीं हुआ इसलिए ट्रम्प सब पर भड़क रहे हैं। ईरान खुद तबाह हो रहा है पर आसपास तबाही मचाने की उसकी क्षमता कायम है। उनकी नीति प्रतीत होती है कि 'हम तो डूबे हैं सनम तुम को भी ले डूबेंगे'। ईरानी वायुसेना और नौसेना तबाह हो चुकी है परउसके पास 3000 मिसाइल और हज़ारों ड्रोन हैं जिन्हें पहाड़ों के नीचे सिलो में रखा गया है जहां अमेरिकी बम नहीं पहुंच सकते। वह महीनों लड़ सकते हैं जिसका अंदाज़ा अमेरिकी नेतृत्व को हो रहा है। अमेरिकियों को भी अहसास हो रहा है कि वह फ़ालतू युद्ध में फंस गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक जॉन मीयरशेमर ने लिखा है, «हम यह संदेश दे रहे हैं कि हम मूर्खों का टोला हैं। हमने वह युद्ध शुरू कर दिया जो हम जीत नहीं सकते»। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस जो ट्रम्प के बड़े समर्थक रहे हैं, ने ख़ुद को इस अभियान से अलग रखा हुआ है। अमेरिका की सैन्य ताक़त की कमज़ोरी खाड़ी के देशों को ईरान के फ़ायर से बचाने में उनकी असफलता से पता चलती है। इन देशों ने अपनी ज़मीन पर अमेरिका के अड्डों की इजाज़त दी हुई है जो उनके लिए मुसीबत बन चुके हैं क्योंकि अमेरिका के अड्डों के कारण उन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। अनुमान है कि यूएई पर 1800 मिसाइल हमले हो चुके हैं। दुबई पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं। इन देशों को मिली कथित अमेरिकी सुरक्षा छतरी की अपर्याप्तता जगजाहिर हो चुकी है। अमेरिकी दूतावासों पर हमले हो रहे हैं और अमेरिकियों को वहां से निकाला जा रहा है।अमेरिका और इज़राइल के मुक़ाबले में ईरान बहुत मामूली ताक़त है पर वह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका राष्ट्रवाद बहुत गहरा और सुदृढ़ है।मध्य पूर्व से रक्षा विशेषज्ञ डैनी सिट्रोनोविक बताते हैं, ईरान के पास जो कुछ है वह उन्होंने लड़ाई में झोंक दिया है ज़्यादा बमबारी से कुछ नहीं बदलेगा। तेल पर दबाव डाल कर वह समझते हैं कि वह अमेरिका को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हर चुनौती बमबारी से हल नहीं हो सकती।जंग की तपिश से सारी दुनिया प्रभावित है। हैरानी है कि अमेरिका ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वियतनाम में कम्युनिस्टों को रोकने के लिए दख़ल दिया गया। विनाशकारी युद्ध में लाखों लोग मारे गए पर अमेरिका को दुम दबा कर वहाँ से भागना पड़ा। इराक़ और लीबिया में दख़ल दिया गया। सद्दाम हुसैन और गद्दाफ़ी को सत्ता से हटा दिया गया पर दोनों देशों की हालत अराजक कर अमेरिका वहां से हट गया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे।

ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम सद्धम्पन्न हुआ

कप्तानगंज(कुशीनगर)।

ग्राम प्रधान/स्थानीय प्राधिकारी,निकायों के सदस्यों का एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी व उन्मुखीकरण कार्यक्रम चकिया के मंशा लान में संपन्न हुआ।इस कार्यक्रम में विनय प्रकाश गोंड विधायक रामकोला मुख्य अतिथि तथा विनोद कुमार गुप्ता उपजिलाधिकारी कप्तानगंज विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम प्रधानों ने सरकारी स्कूलों में कायाकल्प के तहत बहुत अच्छा काम किया है। विनोद कुमार गुप्ता उपजिलाधिकारी कप्तानगंज ने बताया कि SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षकों की बदौलत कप्तानगंज तहसील मंडल में पहले स्थान पर रहा।इस कार्यक्रम के मुखिया खंड शिक्षा अधिकारी डॉ प्रभात चंद राय जी ने सबको संबोधित करते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और शिक्षक आपसी तालमेल से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे और बेसिक स्कूलों की दशा बदल रहे। प्रभात सर ने कप्तानगंज ब्लॉक में कार्यरत ARP गण मोहम्मद सलीम अली, प्रवीण कुमार शुक्ला,त्रिपुरारी नाथ मिश्रा,दिलीप कुमार और विनोद कुमार सिंह को विशेष आभार प्रकट किया,जिनकी देख रेख में निपुण असेसमेंट में कप्तानगंज ब्लॉक ने जनपद पहला स्थान हासिल किया।जिले के SRG श्री राम प्रकाश पाण्डेय और ब्लॉक की ARP टीम ने कायाकल्प और नव भारत साक्षरता,विद्यालय प्रबंध समिति और MDM, निपुण भारत मिशन, ICT लैब,स्मार्ट क्लास,डिजिटल उपस्थिति ,शारदा कार्यक्रम समर्थ और नवीन नामांकन पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए।इस अवसर पर आयोजन स्थल प्रभारी के रूप में राजेश्वर सिंह,दिनेश पाण्डेय,संजीव गोंड,मंचीय व्यवस्था में रजनीश प्रकाश सिंह,मुकुंद देव सिंह,धर्मप्रकाश पाठक,धनंजय पाण्डेय ,मंच संचालन में हरे कृष्ण पाण्डेय,विनयतोष शुक्ला ,रंगोली समिति में ,मनोरमा सिंह,पूजा सिंह,राम आशीष प्रसाद,दीप प्रज्वलन में बलिराम चौहान,मनोरमा त्रिपाठी,मनोरमा सिंह,पूजा मिश्रा,वंदना राव,जलपान प्रभारी में रामाश्रय दुबे,विजय प्रकाश तिवारी,ओंकार सिंह,विनोद ओझा,विनोद कुमार सिंह,रामदयाल जी,विशिष्ट सहयोग समिति में पंकज राय, पुनीत राय ,अनुपम मद्धेशिया,सतीश सिंह और दिनेश शुक्ला जी ,इन सभी बहुत अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इस संगोष्ठी में ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों के साथ साथ राष्टीय सह मेधा छात्रवृति में चयनित बच्चों और नवोदय परीक्षा उत्तीर्ण एक छात्र को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम प्रधानों को भी प्रशस्ति पत्र, शाल और फूल माला के साथ सम्मानित किया गया।

उच्च प्रा वि बड़हरा बाबू,कन्या उच्च प्रा वि कप्तानगंज और कंपोजिट उच्च प्रा वि चकिया के बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।इसी साल सेवा निवृत्त हो रहे दो शिक्षिकाओं श्रीमती रीता विश्वकर्मा और श्रीमती मधुलिका मसीह को खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्मृति चिन्ह और भेंट देकर सम्मानित किया गया। जिला स्काउट मास्टर अंजनी नंदन द्विवेदी और जिला गाइड कैप्टन मनोरमा त्रिपाठी जी ने अपने बच्चों की टीम के साथ माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय का अच्छे से स्वागत किया।मीडिया प्रभारी और जिला महामंत्री ARP संघ मो सलीम अली ने बताया कि इस अवसर पर सभी शैक्षिक संगठनों के अध्यक्ष और मंत्री के साथ साथ समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे।कार्यक्रम में नागेंद्र पाठक , भूतपूर्व अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ का बहुमूल्य योगदान रहा ।

नेबुआ नौरंगिया में प्रेम प्रसंग में युवक की संदिग्ध मौत- अदालत के आदेश पर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नेबुआ नौरंगिया थाना,

कुशीनगर । नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बरवा पूर्दिल गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले मेंक पुलिस ने अदालत के आदेश पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।जानिए पूरा मामला।मृतक युवक सैदुल्लाह की मां अख्तरी उर्फ सोना ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इस बात से नाराज थे और सैदुल्लाह को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मां के अनुसार, 3 जनवरी की शाम करीब चार से छह बजे के बीच जाकिर, रविउल्लाह, तारीफ, आसमा और हसरत ने सैदुल्लाह को रास्ते में रोककर मारपीट की।

उन्होंने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी और उसके परिवार को भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।इस घटना से आहत होकर युवक उसी रात घर लौटा और अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद भी आरोपियों द्वारा उन्हें लगातार धमकियां दी जाती रहीं।मृतक की मां ने बताया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।न्यायालय के निर्देशक रात को पुलिस ने जाकिर, रविउल्लाह, तारीफ, आसमा और हसरत के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति ने पुष्टि की कि न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

युवक को पिस्टल दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल

कुशीनगर।

जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल अकबरपुर गांव में एक युवक को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना का करीब 12 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जंगल अकबरपुर निवासी एम.डी. राज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 16 मार्च 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह घर से दुकान जा रहे थे। इसी दौरान घर से लगभग 150 मीटर दूरी पर गांव के ही विशाल गौतम, आकाश पासवान, इंद्रासन भारती तथा एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से पहुंचे और उन्हें पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए।

एक आरोपी पकड़ा गया, अन्य फरार

पीड़ित के अनुसार घटना के बाद उन्होंने अपने एक परिचित को सूचना दी, जिसके सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए। पकड़े गए युवक के पास से पिस्टल मिलने का भी दावा किया गया है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह

तहरीर में पीड़ित ने बताया कि मुख्य आरोपी से उनकी पुरानी रंजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

कुशीनगर में 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील' अभियान, 31 नमूनों की जांच—एक अशुद्ध पाया गया

कुशीनगर। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II प्रदीप कुमार राय के निर्देशन में एफ.एस.डब्ल्यू. (फूड सेफ्टी ऑन व्हील) सचल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न स्थानों पर जांच और जागरूकता अभियान संचालित किया गया। यह अभियान रविन्द्रनगर धूस (पडरौना), शहीद चौक कसया एवं गांधी चौक कसया में चलाया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बुझावन चौहान ने खाद्य कारोबारियों और आम नागरिकों द्वारा लाए गए खाद्य पदार्थों की मौके पर प्राथमिक जांच की। जांच के बाद संबंधित लोगों को परिणामों से अवगत कराते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों, घरेलू जांच विधियों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। अभियान के दौरान कुल 31 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें 30 नमूने शुद्ध पाए गए, जबकि एक नमूना अशुद्ध मिला। साबुत जीरा में बाहरी तत्व पाए जाने पर संबंधित दुकानदार को कड़ी चेतावनी दी गई। नवरात्रि एवं रामनवमी पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष सघन अभियान भी चलाया। इस दौरान दुकानों और खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने और केवल शुद्ध सामग्री के विक्रय के निर्देश दिए गए। मिलावट की आशंका के आधार पर अन्नापूर्णा ग्रोसरी (रविन्द्रनगर धूस, पडरौना) से सिंघाड़ा आटा व कुट्टू आटा तथा कसया क्षेत्र से साबूदाना सहित कुल चार नमूने जांच के लिए संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कन्हैया लाल वर्मा और राम बुझावन चौहान शामिल रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मलिन बस्तियों से बारीपुर धाम तक सेवा का संकल्प

आर्यावर्त संकल्प सोसाइटी ने कराया भंडारा, महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर

भटनी देवरिया।

जनहित में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही आर्यावर्त संकल्प सोसाइटी द्वारा भटनी क्षेत्र की मलिन बस्तियों एवं देवरिया के बारीपुर धाम स्थित हनुमान मंदिर पर निशुल्क भोजन भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों ने न सिर्फ सेवा भाव का परिचय दिया, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी संदेश दिया। संस्था की प्रवक्ता शिखा श्रीवास्तव ने भंडारा पूर्ण कराते हुए कहा कि वे स्थानीय महिलाओं में चेतना जागृत करने का कार्य निरंतर करती रहेंगी, जब तक हर बालिका स्वयं को सुरक्षित, स्वतंत्र और शिक्षा के प्रति प्रेरित महसूस न करने लगे। उन्होंने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर विशेष जोर दिया।

वहीं संस्था की प्रबंधक अनुराधा बरनवाल ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे घरेलू कार्यों के साथ अपनी आय का स्रोत भी विकसित कर सकें। उन्होंने कहा कि संस्था समाज के दबे-कुचले, शोषित और वंचित वर्ग के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सोसाइटी के सेक्रेटरी अभिषेक मिश्र ने समाज में चेतना के विकास और महिलाओं को जागरूक करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उनके मार्गदर्शन में मलिन बस्तियों में भोजन वितरण तथा धाम पर भंडारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बारीपुर हनुमान मंदिर के महंत, प्रबंधक कैप्टन जयराम यादव, मीना यादव, प्रार्थना राय, वी.के. श्रीवास्तव, शिक्षक विजय रतन श्रीवास्तव, आशुतोष मणि त्रिपाठी, अधीक्षक रामकृपाल, महिला थाना अध्यक्ष पूनम यादव, सुमन पांडेय, प्राचार्य मोहन शर्मा, अधिवक्ता राजकुमार, प्रशांत, विनय मिश्र, पूजा मिश्रा, कीर्ति गुप्ता, सिंधु कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए पत्नी के नाम पर जमीन आवंटन का है मामला

देवरिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी और अधिवक्ता-एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। यह मामला देवरिया जिले में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अमिताभ ठाकुर ने अपनी पत्नी के नाम पर जिला उद्योग केंद्र का एक औद्योगिक प्लाट आवंटित करा लिया था। नूतन ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अदालत में पक्ष रखा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जितेंद्र सिन्हा की एकल पीठ में हुई, जहां अदालत ने नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1999 का है, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लॉट नंबर बी-2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर (तब नूतन देवी) के नाम पर करा दिया था। इस मामले में देवरिया में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि वह लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को भी अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच अब भी जारी है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से ठाकुर दंपति को बड़ी राहत मिली है।

मतदाता सूची शुद्धिकरण में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम-डॉ अरविंद शर्मा

गोहाना(सोनीपत)।

सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केवल बीएलए-1 और बीएलए-2 ही नहीं, बल्कि प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने बूथ सम्भाले थे, उसी प्रकार अपने-अपने इलाके में एसआईआर प्रक्रिया को पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएं। वीरवार को सैक्टर 7 स्थित भाजपा जिला गोहाना की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार कार्यकर्ता चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर सजग रहते हैं, उसी प्रकार SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया

-एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान, विपक्ष पर लगाए दोहरे मापदंड के आरोप

-जनसमर्थन खो रहा है विपक्ष, इसलिए कर रहे हैं विरोध

-कैबिनेट मंत्री ने गोहाना रैली की तैयारियों पर भी पदाधिकारियों के साथ की चर्चा

के दौरान भी चौकसी बरतना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी मतदाता का नाम दो जगह न हो, मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटें, स्थान बदल चुके मतदाताओं का नाम सही स्थान पर दर्ज हो तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र युवाओं के नाम सूची में जोड़े जाएं। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि 19 फरवरी को 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और हरियाणा में 24 वर्षों बाद यह प्रक्रिया हो रही है। वर्तमान में प्री-एसआईआर के तहत वर्ष 2002 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2025 की सूची से किया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा द्वारा विधानसभा स्तर पर बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं और बूथ स्तर पर बीएलए-2 की नियुक्ति अंतिम चरण में है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण लगातार हार रहा है और अब ईवीएम पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में कांग्रेस के समय ही ईवीएम से चुनाव हुए थे और तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। अब हार के बाद ईवीएम को दोष देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों ने चुनाव आयोग को कोई ठोस सुझाव नहीं दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के -डिटेक्ट,

वर्तमान में प्री-एसआईआर के तहत वर्ष 2002 की मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2025 की सूची से किया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

डिलीट और डिपोर्ट के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीति स्पष्ट है। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे चुनाव जीतते हैं तो मतदाता सूची सही होती है और हारने पर उसे गलत बताया जाता है। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर सवाल उठाकर विपक्ष देश की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी डॉ. किरण कलकल, जिलाध्यक्ष बिजेन्द्र मलिक, मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्ण सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष भलेराम नरवाल व डॉ. धर्मवीर नांदल, योगेश दत्त, इंद्रजीत सिरमानी, बलराम कौशिक, डॉ. रमेश कश्यप, डॉ. ओमप्रकाश शर्मा, गोहाना विधानसभा बीएलए राजू पटवा, बरोदा विधानसभा बीएलए 1 सतपाल लठवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीना शर्मा, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेश खानपुर, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पवन शर्मा सरपंच, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश रोहिल्ला, नरेन्द्र गहलावत, नितेंद्र शर्मा, महेन्द्र चिड़ाना, रामेश्वर राठी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे।

शांति के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी जरूरी- पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की. पीएम मोदी ने बताया, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से पश्चिम एशिया की स्थिति और तनाव कम करने की तत्काल जरूरत के साथ-साथ बातचीत और डिप्लोमेसी की ओर लौटने के बारे में बात की. पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की और ओमान के लोगों को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम इस बात पर सहमत हुए कि तनाव कम करने और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है. हमने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भारत की निंदा को दोहराया और भारतीय नागरिकों सहित हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में ओमान के प्रयासों की सराहना की. भारत और ओमान स्टेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित और फ्री मूवमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं. पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से बात की और ओमान के लोगों को ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दीं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम इस बात पर सहमत हुए कि तनाव कम करने और उसके बाद शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है. हमने ओमान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भारत की निंदा को दोहराया और भारतीय नागरिकों सहित हजारों लोगों की सुरक्षित वापसी में ओमान के प्रयासों की सराहना की. भारत और ओमान स्टेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित और फ्री मूवमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उत्तम नगर में ईद के मौके पर माहौल न बिगड़े, कड़ी हो सुरक्षा

नई दिल्ली।

ईद के दौरान हिंसा रोकने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस सहित अन्य से जवाब मांगा है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया है कि याचिका में कानून-व्यवस्था की उस संभावित स्थिति से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और याचिका में ईद के दिन इससे सार्वजनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। अदालत ने यह भी रिकॉर्ड पर लिया कि याचिका में व्यक्त की गई आशंका चार मार्च को होली के दिन उत्तम नगर में एक युवक की हत्या के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण हुई। मृत्यु के कारण विभिन्न समुदायों से संबंधित लोगों में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके कारण समाज के कुछ वर्ग ईद के अवसर पर हिंसा कर सकते हैं और ऐसी स्थिति से बचा जाना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि पुलिस ने यह भी बताया है कि इलाके में सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। चार कंपनी में 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। पुलिस ने बताया है कि इंटरनेट मीडिया पर निगरानी भी रखी जा रही है और 8862 लोगों को सत्यापित किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार अमन कमेटी बैठक जिला स्तर पर की जा चुकी है।

पिछले दो सप्ताह में इस तरह की 36 बैठक की जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया कि द्वारका पुलिस ने कानून-व्यवस्था के संबंध में कई कदम उठाए हैं।

ईद का त्योहार खुशी मनाने के लिए

अदालत ने कहा कि ईद का त्योहार खुशी मनाने के लिए मनाया जाता है और यह सभी संबंधित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस पवित्र अवसर पर किसी भी व्यक्ति या समाज के किसी भी वर्ग द्वारा की गई तोड़-फोड़ या गुंडागर्दी जैसी किसी भी अप्रिय घटना के कारण जनजीवन बाधित न हो।

पुलिस को बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी

अदालत ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार और पुलिस का कर्तव्य है कि समाज का हर नागरिक अपने धार्मिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करे। याचिका में जताई गई आशंका चार मार्च को हुई घटना पर आधारित है और इसलिए पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। पीठ ने कहा कि अदालत इस बात पर जोर देती है कि स्थिति का आकलन करने पर यदि पुलिस बंदोबस्त को और मजबूत करने की कोई आवश्यकता महसूस होती है, तो तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस और सरकार को हाई कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

ईद हिंसा रोकने की याचिका पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा।

होली पर हत्या के बाद हिंसा की आशंका जताई गई।

पुलिस ने 400 कर्मी तैनात किए, सोशल मीडिया निगरानी जारी।

कड़ी निगरानी रखें सरकार और पुलिस

अदालत ने पुलिस और सरकार को लगातार कड़ी निगरानी रखने का आह्वान करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के सदस्यों से भी संयम बनाए रखने और इस तरह से आचरण करने का आह्वान किया, जिससे शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले और ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जो विकट रूप ले ले।

कानून के तहत सभी उचित कदम उठाए पुलिस

अदालत ने उक्त टिप्पणियों के साथ कहा कि हम इस क्षेत्र की पुलिस और नागरिक प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वे कानून के तहत अनुमेय सभी आवश्यक कदम उठाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिति कोई अप्रिय मोड़ न ले। अदालत ने कहा कि पुलिस का बंदोबस्त इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सभी लोगों में सुरक्षा और संरक्षा की भावना पैदा हो। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी शरारत करने की अनुमति न दी जाए।

6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, रामनवमी तक लागू रहेगी व्यवस्था

अदालत ने निर्देश दिया कि इलाके में की गई सुरक्षा व्यवस्था रामनवमी तक लागू रहेगी। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी। अदालत ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता संजय लाओ से कहा कि पुलिस से कहें की कोई कमी न रहे।

50 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर सीएम ममता ने भाजपा को घेरा, बताया अघोषित आपातकाल

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल को जान-बूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने 50 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को अघोषित आपातकाल करार दिया। एक्स पर पोस्ट लिखते हुए सीएम बनर्जी ने दावा किया कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने बंगाल को अलग करके निशाना बनाया है, वह पहले कभी नहीं हुआ, यह बेहद चिंताजनक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा यह कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उच्चतम स्तर की राजनीतिक दखलंदाजी है। उन संस्थाओं का व्यवस्थित राजनीतिकरण, जिन्हें निष्पक्ष रहना

चाहिए, संविधान पर सीधा हमला है। ऐसे समय में जब एक बेहद दोषपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और 200 से ज्यादा लोगों की जान पहले ही जा चुकी है, आयोग का रवैया साफ तौर पर पक्षपात और राजनीतिक हितों के प्रति एक असहज समर्पण को दिखाता है, जिससे बंगाल के लोगों को लगातार खतरा बना हुआ है। पूरक मतदाता सूचियां अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की साफ अवहेलना है, जिससे नागरिक चिंतित और अनिश्चित हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसी एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों का जान-बूझकर तबादला किया जा रहा है ताकि राज्य के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर किया जा सके। उन्होंने पूछा, भाजपा इतनी बेचैन क्यों है? बंगाल और उसके लोगों को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आजादी के 78 साल बाद भी नागरिकों को लाइनों में खड़े होकर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करने से उन्हें क्या संतोष मिलता है? स्थिति को अघोषित आपातकाल बताते हुए सीएम ने कहा यह कोई संयोग नहीं है, यह जबरदस्ती और संस्थागत हेरफेर के जरिए पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण पाने की एक सोची-समझी साजिश की ओर इशारा करता है।

सिर्फ भाजपा ही खून-खराबा चाहती है - उत्तम नगर में भड़की हिंसा पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी पर आरोप लगाया

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर उत्तम नगर घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है। गांधी ने दिल्ली के निवासियों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील की। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने उत्तम नगर झड़प को लेकर कहा कि लोगों को इस हिंसा की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक तरफ तरुण नामक जवान लड़के की जान चली गई। दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा कि खून-खराबा केवल भाजपा और उसका इकोसिस्टम चाहता है। यह नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने का हर मौका भुनाता है। उन्होंने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा देश को हिंदू-मुसलमान में उलझाए रखना चाहती है। उनका मानना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग प्रधानमंत्री से सवाल न पूछ सकें। ये सवाल देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं। साथ ही सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर भी सवाल न उठें। इसीलिए राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्लीवासियों से किसी भी बहकावे में न आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में निहित है। गांधी ने अपने संदेश में -जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो का नारा भी दिया। उन्होंने शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया।

नोएडा एयरपोर्ट का इंतजार खत्म, 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन; सीएम योगी का न्योता स्वीकार

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें कि यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और एशिया स्तर का प्रमुख हवाई अड्डा बनेगा, जो पहले चरण में एक रनवे और टर्मिनल के साथ सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखेगा। बाद में इसे पांच रनवे तक विस्तारित किया जाएगा। हाल ही में इसे एयरोड्रम लाइसेंस भी मिल चुका है। उद्घाटन से दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, साथ ही ग्रेटर

नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि इलाकों में कनेक्टिविटी, रोजगार, निवेश और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार को इससे करीब 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। शुरुआत में रोजाना 150 फ्लाइट्स संचालित हो सकती हैं। यह उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

पश्चिम एशिया संकट: सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी मुश्किल समय- विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक संपर्क तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह समय सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का है। उन्होंने बताया कि भारत के नेता विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और शांति व स्थिरता के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं।

इस्राइली हमलों के बाद ईरान का पलटवार खाड़ी में कई रिफाइनरी को बनाया निशाना

तेहरान। ईरान ने गुरुवार को खाड़ी क्षेत्र के अरब पड़ोसी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए। यह कदम इस्राइल की ओर से उसके मुख्य अपतटीय गैस क्षेत्र पर किए गए हमले के जवाब में उठाया गया। ईरान ने लाल सागर में सऊदी अरब की एक रिफाइनरी पर हमला किया और कतर की एलएनजी सुविधाओं तथा कुवैत की दो तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। इससे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध गंभीर स्थिति में पहुंच गया है और दुनियाभर में ईंधन की कीमतें तेजी से वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। 28 फरवरी को इस्राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, इसके बाद से इसमें 57 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऊर्जा संकट की आशंका के कारण बाजारों में चिंता बढ़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तट के पास एक जहाज में आग लग गई और कतर के पास एक अन्य जहाज को नुकसान पहुंचा। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य पर मंडराते खतरे की ओर ध्यान गया, जहां से दुनिया के तेल का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है और जिस पर ईरान का प्रभाव है। सऊदी अरब पहले ही इस जलमार्ग से बचने के लिए तेल को पश्चिम की ओर लाल सागर के रास्ते भेज रहा था, लेकिन यनबू शहर में स्थित उसकी सैमरेफ रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद इस रास्ते की सुरक्षा पर भी सवाल उठ गए हैं। कतर ने बताया कि उसकी एक बड़ी एलएनजी सुविधा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले के हमलों के कारण उत्पादन पहले ही बंद था।

लेकिन नए हमलों से वहां और ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे युद्ध खत्म होने के बाद भी कतर की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कतर दुनिया के लिए प्राकृतिक गैस का एक बड़ा स्रोत है।

कुवैत में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला

कुवैत की मीना अल-अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इसके कुछ ही समय बाद पास की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी में भी आग लग गई।

हमलों से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया- सऊदी राजनयिक

अबू धाबी के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें हबशान गैस सुविधा और बाब फील्ड में काम बंद करना पड़ा। उन्होंने इसे ईरान के हमलों को खतरनाक बढ़ोतरी बताया। खाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों में मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजे और इस्राइल ने भी कई बार ईरानी हमलों की चेतावनी दी। कतर, सऊदी अरब और यूएई ने इन हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि इन हमलों से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया है।

इस्राइल में सुरक्षित ठिकानों पर गए लाखों लोग

इस्राइल में भी ईरान के कई हमलों के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन बड़े पैमाने पर जनहानि की खबर नहीं है। ईरान ने ये हमले तब किए, जब इस्राइल ने दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है और कतर के साथ साझा किया जाता है। यह हमला ईरान की बिजली आपूर्ति के लिए भी खतरा माना जा रहा है क्योंकि देश की ज्यादातर बिजली प्राकृतिक गैस से बनती है।

पेजेशकियन और ट्रंप ने क्या कहा?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने चेतावनी दी कि इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान कतर के ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रखता है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा।

कतर की एलएनजी सुविधा पर मिसाइल हमला

इस बीच, कतर की रास लाफान एलएनजी सुविधा पर मिसाइल हमले से आग लग गई। कतर के तट के पास एक जहाज भी प्रभावित हुआ। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उसे सीधे निशाना बनाया गया या मलबे से नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान अब तक 20 से ज्यादा जहाजों पर हमले हो चुके हैं, क्योंकि ईरान इस अहम जलमार्ग पर सख्त नियंत्रण बनाए हुए है। ईरान का कहना है कि यह मार्ग खुला है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नहीं।

उच्च शिक्षा विधेयक पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल, संघीय ढांचे के उल्लंघन का लगाया आरोप

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने गुरुवार को प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को लेकर गंभीर चिंता जताई और आरोप लगाया कि यह संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस विधेयक को लेकर सात प्रमुख आपत्तियां गिनाईं। जिनमें राज्यों से परामर्श न करना, संवैधानिक अतिक्रमण, फंडिंग काउंसिल का अभाव, उच्च शिक्षा का बढ़ता नौकरशाहीकरण और यूजीसी की परामर्श प्रक्रिया का कमजोर होना जैसे आरोप शामिल हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए उच्च शिक्षा की पूरी संरचना को फिर से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। यह विधेयक फिलहाल संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। जयराम रमेश ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यूजीसी और एआईसीटीई जैसे प्रमुख नियामक संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियां सामने आई हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद इस विधेयक के मसौदे में राज्य सरकारों से कोई परामर्श नहीं किया गया, जबकि इसका सीधा असर राज्य विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा।

कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के दायरे से आगे जाकर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। पार्टी के अनुसार, विश्वविद्यालयों के गठन और संचालन से जुड़े विषय राज्य सूची में आते हैं, इसलिए यह विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा परिषद के चार स्तंभों की परिकल्पना की गई थी, जबकि इस विधेयक में केवल तीन काउंसिल का प्रस्ताव है

और अनुदान देने वाली संस्था का प्रावधान नहीं है। उनका आरोप है कि इससे वित्तीय शक्तियां स्वायत्त शैक्षणिक निकायों से हटकर सीधे मंत्रालय के पास चली जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का संचालन शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, लेकिन नए विधेयक में प्रशासनिक नियंत्रण नौकरशाहों के हाथ में देने का प्रस्ताव है, जो शिक्षा के लिए ठीक नहीं है।